

ईरान-अमेरिका-इज़रायल युद्ध भारत के तट तक पहुँचा!

अमेरिका की पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत को, भरत की जल सीमा से 40 किलोमीटर दूर डुबोया, श्रीलंका की जल सेना ने युद्धपोत के 32 नाविकों को डूबने से बचाया तथा 80 नाविक डूब गए

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 मार्च। ईरान-अमेरिका-इज़रायल युद्ध अब खतरनाक रूप से हमारे क्षेत्र के करीब आता जा रहा है। श्रीलंका के तट से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक ईरानी युद्धपोत को अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया। जहाज पर सवार लगभग 80 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और अब तक चालक दल के सदस्यों में से केवल 32 को बचाया जा सका है।

नाटो गठबंधन में भी दरारें दिखाई देने लगी हैं। स्पेन ने ईरान में सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिकी वायुसेना को अपने हवाई अड्डों के उपयोग की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस इनकार से नाराज होकर ट्रंप ने स्पेन के साथ सभी व्यापारिक संबंध निलंबित करने और डंडात्मक कदम उठाने की धमकी दी है।

इसके साथ ही, यह क्षेत्रीय युद्ध अब मध्य पूर्व से बहुत आगे तक फैल रहा है, क्योंकि ईरानी युद्धपोत युद्ध क्षेत्र से हजारों मील दूर था। सवाल उठता है

- अहमू सवाल है, क्या अमेरिका, यह दुःसाहस पूर्ण आक्रमण करने की हिम्मत दिखाता, अगर, ईरानी युद्धपोत, चीन या रूस की सीमा के इतना ही नज़दीक होता, जितना भारत की जल सीमा के नज़दीक था।
- अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में छाती ठोकते हुए गर्व से कहा कि अमेरिका यह युद्ध बेरहमी से जीतता जा रहा है और युद्ध के दिनों में “शत्रु” के जहाजों पर आक्रमण करना जायज होता है।
- पर, अहमू सवाल है, युद्धपोत, भारत की जल सीमा में था या अंतर्राष्ट्रीय पानी में।
- विश्व का 20 प्रतिशत ऑयल, स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ के जरिए आता-जाता है।
- फिलहाल, स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ पर ईरान का आधिपत्य है, अमेरिका दावा कर रहा है कि वो शीघ्र ही इस स्ट्रेट के मार्फत आवागमन सामान्य कर देगा और इस स्ट्रेट के जरिए आवागमन को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका की नौ-सेना द्वारा “एस्कॉर्ट” कर देगा।
- फिलहाल ईरान ने टर्कों में नाटो के एयरबेस और कतर में अमेरिका के ठिकानों पर आक्रमण कर दिया है और 1.2 अरब डॉलर का अमेरिका का आधुनिकतम राडार सिस्टम भी नष्ट कर दिया है।

कि क्या अमेरिका ऐसा ही कदम उठाता, यदि यह जहाज चीन या रूस के जलक्षेत्र के पास होता।

चीन और रूस, दोनों देश ईरानी शासन और उसके अस्तित्व के मजबूत

समर्थक हैं। चीन के ईरान में महत्वपूर्ण हित है, क्योंकि चीन ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है। ईरान ने होरमुज़ जलडमरूमध्य को बेराबंदी में लेने की कोशिश की है। यह जलडमरूमध्य तेल

आपूर्ति के लिए जीवनरेखा है, क्योंकि दुनिया के कुल तेल परिवहन का लगभग 20 प्रतिशत इसी रास्ते से गुजरता है। अब तक होरमुज़ जलडमरूमध्य (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ब्रिटेन के एक अखबार, फायनैंशियल टाइम्स ने इसके साथ यह भी खुलासा किया कि इसी वजह से खामनेई मारे गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इज़रायल कई वर्षों से इसी काम में लगा हुआ था।

शनिवार को इसी क्षेत्र पर हुए हमले में खामनेई मारे गए थे। यह खुलासा ब्रिटिश अखबार “फाइनैंशियल” की एक रिपोर्ट में किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, एक कैमरे का कोण विशेष रूप से उपयोगी साबित हुआ, जिसने कड़ी सुरक्षा वाले परिसर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व विदेश मंत्री दिनेश सिंह की कुर्बानी, प्रमाण है, ईरान के विशेष महत्व का

1994 में पाकिस्तान ने सभी इस्लामिक देशों को लामबंद कर लिया था, कश्मीर में मानवाधिकार हनन के आरोप लगाकर यूएन में भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए

-नेपु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 मार्च। भारत के कुछ वर्गों में यह धारणा जोर पकड़ रही है कि ईरान कभी भारत का सच्चा मित्र नहीं रहा और उसने कभी भारत के साथ खड़े होकर समर्थन नहीं दिया, तो फिर भारत को ईरान के समर्थन में खुलकर आगे आने की क्या आवश्यकता है। यह बात इस संदर्भ में कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई के निधन पर कोई बयान नहीं दिया, और इसे मोदी सरकार द्वारा सामान्य माना जा रहा है।

लेकिन यह असली कहानी नहीं है। असल में अप्रैल 1994 में पाकिस्तान ने ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआईसी) के सदस्य देशों को अपने एक प्रस्ताव के समर्थन में एकजुट कर लिया था, जिन्हें वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के

- तत्कालीन विदेश मंत्री दिनेश सिंह को, जो गंभीर रूप से बीमार थे, रोग शैया से उठाकर व्हील चेयर पर बिठाकर, हवाई जहाज से सीधे ईरान भेजा गया, ईरान को इस्लामिक संगठन के इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से रोकने के लिए।
- दिनेश सिंह ने तत्कालीन प्र.मंत्री नरसिम्हाराव का विशेष पत्र, ईरान के शीर्षस्थ नेता को व्यक्तिगत रूप से पेश किया।
- ईरान ने प्र.मंत्री राव की “रिक्वैस्ट” की गंभीरता को समझते हुए, इस्लामिक देशों के संगठन के आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया और इस्लामिक देशों के संविधान के अनुसार, जब तक सभी सदस्य किसी भी ऐसे प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित नहीं करते, वह प्रस्ताव क्रियान्विति के लिए यूएन को नहीं दिया जा सकता था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत और चीन ने खामनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?

दोनों देशों ने इस मामले पर बहुत संयमित और नपी तुली प्रतिक्रिया दी है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 मार्च। सप्ताहांत में अमेरिका-इज़राइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भारत में तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विपक्ष ने इस पर सरकार से औपचारिक बयान जारी करने की मांग की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अब तक संयमित चुप्पी बनाए रखी है और किसी बयान के बजाय, क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच संयम बरतने और “डी-एस्केलेशन” की अपील की है। सूत्रों के अनुसार, यह रुख अधिकांश प्रमुख वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया के अनुरूप है।

चीन के ईरान के साथ गहरे ऊर्जा संबंध अचानक कड़ी निगरानी में आ गए हैं, क्योंकि अमेरिकी और इज़रायली हमलों ने तेहरान को खुली टकराव की स्थिति में ला खड़ा किया है और उन तेल

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयम बरतने और बातचीत कर समाधान करने की बात कही और चीन ने भी युद्ध की निंदा की तथा युद्ध विराम लागू करने की मांग की।
- चीन के ईरान के साथ गहरे ऊर्जा संबंध हैं और इस टकराव से तेल आपूर्ति के रास्ते बाधित हो गए हैं, जिन पर चीन की अर्थव्यवस्था निर्भर है।
- लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की बात करें तो जी-7 के किसी भी देश ने खामनेई की मौत पर शोक नहीं जताया तथा कई अन्य देशों की तरफ से खामनेई को “ईविल” व्यक्ति बताया जा रहा है।

आपूर्ति मार्गों को खतरे में डाल दिया है, जिन पर चीनी अर्थव्यवस्था निर्भर है। बीजिंग ने हमलों की निंदा और युद्धविराम की अपील की है, लेकिन उसने ऐसी कोई आर्थिक जवाबी कार्रवाई नहीं की है, जो उसकी ऊर्जा आपूर्ति को जोखिम में डाल दे, जिस पर

वह निर्भर है। बीजिंग के लिए सबसे खतरनाक कारक होर्मुज़ जलडमरूमध्य है। चीन के लगभग 44 प्रतिशत तेल आयात विस्तृत पश्चिम एशिया क्षेत्र से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दुबई एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या 1200 से 20 हुई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 मार्च। पश्चिम एशिया के रास्ते हवाई यात्रा इस समय अभूतपूर्व अव्यवस्था का सामना कर रही है। हवाई क्षेत्र व्यापक रूप से बंद हो जाने के कारण उड़ानों का निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन

- फ्लाइट ट्रेडर 24 द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए और कहा गया, यह भारी गिरावट ईरान अटैक के कारण आई है।

और यात्रियों में भारी अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हवाई अड्डों में दुनिया के सबसे व्यस्त विमानन केंद्रों में दुबई इन्टरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है, जो लगभग ठप हो गया है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के साथ ही, कई देशों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हालांकि, युद्ध बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं है, पर, अभी भी कई बड़े देश इसमें सीधे शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए अभी कुछ गुंजाइश बाकी है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 मार्च। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया का युद्ध दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रहा है। इसका सीधा जवाब यह है कि हालांकि तनाव बढ़ने का खतरा निश्चित रूप से बढ़ गया है, लेकिन मौजूदा संघर्ष अभी उन परिस्थितियों तक नहीं पहुँचा है, जो आमतौर पर किसी वैश्विक युद्ध को परिभाषित करती हैं। इस समय टकराव का केन्द्र अमेरिका, इज़रायल और ईरान है। यह संघर्ष तीव्र है, इसमें उन्नत हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, और इसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट और हवाई सेवाओं को प्रभावित कर दिया है। लेकिन विश्व युद्ध के लिए कुछ और भी जरूरी होता है:

- अगर, चीन और रूस इसमें ईरान की तरफ से मैदान में उतरते हैं और नाटो देशों को भी युद्ध में घसीट लिया जाता है, तो हालात नाटकीय रूप से बदल जाएंगे, पर, अभी तक बीजिंग और मॉस्को ने कूटनीतिक रूख ही प्रकट किया है।
- अस्सी के दशक के ईरान-इराक युद्ध, सन् 1991 में अमेरिका की इराक में घुसपैठ महाशक्तियों के टकराव का रूप नहीं ले सकी, यहाँ तक सीरियाई गृह युद्ध भी विश्व युद्ध का रूप ले सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ।
- आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अच्छी तरह से जानती है कि परमाणु ताकतों की भिड़त का कितना भारी दुष्परिणाम हो सकता है।
- इसके अलावा आर्थिक रूप से परस्पर सहनिर्भरता भी एक बड़ा कारण है, जो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को हतोत्साहित करती है। महाशक्तियां जानती हैं कि लम्बे युद्ध से तेल का प्रवाह रुकेगा, ट्रेड रूट नष्ट होंगे और फायनैंशियल मार्केट तबाह हो जाएगा।

कई बड़ी शक्तियों का अलग-अलग क्षेत्रों में एक-दूसरे से सीधा मिलिटरी संघर्ष। यह लिमिट अभी पार नहीं हुई है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अन्य बड़ी शक्तियाँ सैन्य रूप से

इस संघर्ष में प्रवेश करेंगी। यदि चीन या रूस जैसे देश ईरान के समर्थन में सीधे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खामेनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम स्थगित

तेहरान, 04 मार्च। तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम दर्शन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। उनका अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, इसकी नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। ईरान की तसनीम समाचार एजेंसी के

- इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की संभावना है तथा अमेरिका है कि अमेरिका-इज़रायल इस भीड़ पर हमला कर सकते हैं।

मुताबिक, खामेनेई की वसीयत के मुताबिक, उन्हें ईरान के मशहद शहर में सुपुरई-ए-खाक किया जाएगा। हाल ही में इज़रायल और अमेरिका के हमले में उनकी मौत हो गई थी।

बुधवार को ईरानी टेलीविजन ने बताया कि शहीद इमाम के अंतिम दर्शन समारोह को स्थगित कर दिया गया है (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 मार्च। वरिष्ठ पत्रकार हरि कृष्ण दुआ के बुधवार दोपहर 88 वर्ष की आयु में निधन के बाद, श्रद्धांजलियों का सिलसिला शुरू हो गया। पूर्व राजनयिक दुआ को एनडीए और यूपीए, दोनों सरकारों के दौरान सेवाएँ देने की विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त थी। उन्होंने चार राष्ट्रीय दैनिकों का संपादन किया। पद्म भूषण से सम्मानित दुआ ने “हिन्दुस्तान टाइम्स”, “द टाइम्स ऑफ इंडिया”, “द इंडियन एक्सप्रेस” तथा “द ट्रिब्यून” में संपादकीय नेतृत्व संभाला। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में वे कांग्रेस-नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी हिस्सा रहे।

उनके परिवार के एक सदस्य ने बताया कि उन्होंने आज दोपहर एक निजी अस्पताल में शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे और तीन सप्ताह पहले अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। वे अपनी पत्नी अर्पिता और पुत्र प्रशांत को पीछे छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को लोधी रोड श्मशान घाट पर किया जाएगा। 1 जुलाई 1937 को जन्मे दुआ दो प्रधानमंत्रियों, अटल बिहारी वाजपेयी और एच डी देवेगौडा के मीडिया सलाहकार भी रहे। उन्होंने 2001 से 2003 के बीच डेनमार्क में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवा दी। भारतीय पत्रकारिता की एक

- वे उन चंद लोगों में से हैं, जिन्होंने यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों के साथ काम किया है। दुआ एनडीए के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और यूपीए के प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के मीडिया सलाहकार थे, यही नहीं, 2001-2003 तक वे डेनमार्क में भारत के राजदूत भी थे।
- पत्रकारिता में दुआ बेहद प्रतिष्ठित हस्ती थे। 2003 से 2009 तक ट्रिब्यून के एडिटर इन चीफ के रूप में काम कर उन्होंने अखबार को नई ऊंचाइयां दीं, वे हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया को भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
- दुआ के निधन पर विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने शोक जताया और संवेदनाएं प्रकट कीं। दुआ अपने पीछे पत्नी व पुत्र छोड़ गए हैं।

दिग्गज शख्सियत के रूप में दुआ अपनी संपादकीय स्वतंत्रता और तीक्ष्ण

राजनैतिक अन्तर्दृष्टि के लिए व्यापक रूप से प्रतिष्ठित थे।

वे 2003 से 2009 तक “द ट्रिब्यून” के प्रधान संपादक रहे और इस दौरान उन्होंने अखबार की राष्ट्रीय पहचान और संपादकीय विश्वसनीयता को मजबूत किया। अपने लंबे और विशिष्ट करियर में उन्होंने “द इंडियन एक्सप्रेस”, “द टाइम्स ऑफ इंडिया” और “द हिंदुस्तान टाइम्स” में भी वरिष्ठ संपादकीय भूमिकाएँ निभाईं। 2009 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, जहाँ उन्होंने मीडिया की स्वतंत्रता और सार्वजनिक नीति से जुड़ी बहसों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजनीतिक दलों के नेताओं और मीडिया जगत के सदस्यों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए, उन्हें सिद्धांतवादी संपादक और लोकतांत्रिक

मूल्यों के दृढ़ रक्षक के रूप में याद किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, “एच. के. दुआ के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएँ। वे एक विशिष्ट पत्रकार, राजनयिक और पद्म भूषण सम्मानित व्यक्तित्व थे, जिनकी सत्य, संपादकीय स्वतंत्रता और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता ने सार्वजनिक विमर्श को समृद्ध किया।” शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि दुआ ने अहिंसक ईमानदारी, सुतीक्ष्ण दृष्टि और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संपादकीय स्वतंत्रता को कायम रखा। बादल ने कहा, “एक पत्रकार और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एमवीए ने शरद पवार को प्रत्याशी बनाया

मुंबई, 04 मार्च। महाविकास अघाड़ी (एमवीए) की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार को संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया गया है। पवार गुरुवार को

- राज्यसभा चुनावों में महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन को जो एक सीट मिल रही है, उसके लिए शरद पवार चुनाव लड़ेंगे।

राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरेंगे। राकांपा एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को संयुक्त पत्रकार वार्ता में बताया कि उन्होंने शरद पवार को फिर से राज्यसभा में भेजने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से चर्चा की थी। इन सभी नेताओं ने शरद पवार को महाविकास अघाड़ी का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

